निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारेह
विज्ञान भवन, नई दिल्ली
23 मार्च, 2006

डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह
ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार
का अभिभाषण

महामहिम राष्ट्रपति जी, डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम साहब हमारे सहयोगी मंत्री श्री नरेन्द्र जी एवं श्रीमती पाटिल जी, सचिव श्रीमती सुनीला बसंत जी एवं श्रीमती रेणुका विश्वनाथन जी, राज्यों से आए मंत्रीगण, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं विदेशी संस्थाओं के अधिकारी, निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता एवं सरज़मीन से जुड़े हुए पंचायत प्रतिनिधि, पत्रकार बंघुगण एवं उपस्थित बहनों एवं भाइयों ।

आज का दिन अत्यंत गौरव का दिन है कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण करने के लिए उपस्थित हैं । मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण करने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकारा है एवं यहां उपस्थित होकर हमारा उत्साहवर्घन किया है । मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है विगत वर्ष जहां सिर्फ 40 पंचायती राज संस्थाओं को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था आपकी प्रेरणा से इस वर्ष वह संख्या बढ़कर 770 हो गई है । निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण करके आपने सर जमीन से जुड़े कार्यकर्त्ताओं को भी अनुप्राणित किया है ।

विगत वर्ष निर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिये गए अपने अभिभाषण में आपने हम सबके सामने कुछ विशेष लक्ष्य रखे थे । मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो लक्ष्य आपने हमारे सामने रखे थे उस दिशा में हम काफी हद तक अग्रसर हुए हैं एवं इस बारे में आपको विभाग द्वारा उठाए गए विशेष कदमों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा । सम्पूर्ण स्वच्छता

अभियान को करीब सारे देश में लागू कर दिया है एवं फिलहाल 559 जिलों में अनुमोदित कर दिया गया है । इस वर्ष 81 जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है एवं जो थोड़े बहुत बचे हुए जिले हैं उन्हें अगले वर्ष तक इस अभियान में ले जाया जाएगा । आपने बिहार और उत्तरप्रदेश क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए एक विशेष आह्वान किया था एवम् इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान इन दोनों राज्यों के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है । सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय संचार एवम् क्षमता विकास एकक का गठन कर दिया गया है। संभाग एवं जिले स्तर पर भी इन राज्यों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो इस कार्यक्रम को चलाने में अहम् भूमिका निभा रहे हैं । स्वच्छता कार्यक्रम की गति को और कई गुणा बढ़ाने की आवश्यकता है, फिर भी विगत वर्ष में अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं जिसका नतीजा है कि आज पहली बार उत्तर प्रदेश और बिहार में 40 एवं 4 पंचायतें क्रमशः इस पुरस्कार को प्राप्त कर रही हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी प्रेरणा से अगले वर्ष इन राज्यों में ओर कई पंचायतें निर्मल ग्राम पंचायतें हो जाएंगी ।

विगत वर्ष आपने अपने अभिभाषण में ठोस एवं तरल अवशिष्ट पदार्थों के सही निपटान पर विशेष बल दिया था एवं विभिन्न राज्यों के अपने अनुभवों से हमको अवगत कराया था । हमारे विभाग के अधिकारियों ने आपके कहे अनुसार सभी मॉडलों का जमीन पर अवलोकन किया है एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा निर्देश में ठोस एवं तरल अवशिष्ट निपटान हेतु बजट का 10 प्रतिशत आबंटित कर दिया गया है । इस हेतु मंत्रालय ने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले सम्बन्धी समिति का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।

हम सब का यह मानना है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं पूरा तरह उपलब्ध हों एवं खुले में शौच की प्रथा से राष्ट्र मुक्त

हो । इस दिशा में सम्पूर्ण देश को एक जुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है । मुझे खुशी है कि सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य की गति विगत वर्ष में बढ़ी है एवं अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है । इसके परिणामस्वरूप स्वच्छता का आच्छांदन जो वर्ष 2001 में सिर्फ 22 प्रतिशत था आज बढ़कर के लगभग 38 प्रतिशत हो गया है । विगत एक वर्ष में 84 लाख से भी ज्यादा घरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है । मुझे उम्मीद है अगले वर्ष में और भी ज्यादा घरों में यह अभियान पहुंच पाएगा । इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास सिर्फ शौचालयों का निर्माण नहीं बल्कि उनका लगातार इस्तेमाल एवं स्वच्छता सम्बन्धी स्वभाव परिवर्तन पर विशेष बल देना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्वच्छता पर भी विशेष महत्व दिया जा रहा है एवं हमारे विभाग ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2006-07 तक प्रत्येक ग्रामीण सरकारी विद्यालय में स्वच्छता एवं पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं । छात्राओं को खासकर स्वच्छता हेतु ब्लॉक निर्माण पर बल दिया जा रहा है एवं धनराशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 6.57 लाख स्कूल स्वच्छता ब्लॉक निर्माण के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है एवं 2.08 लाख से ज्यादा टॉयलेट ब्लॉकों का निर्माण हो चुका है ।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत यह तय किया गया है कि वर्ष 2015 तक स्वच्छता सुविधाओं के बगैर रहने वाले लोगों की संख्या आधी कर दी जाए । इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए हम सब इतने लम्बे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि सहस्राब्धि विकास लक्ष्य को वर्ष 2010 तक प्राप्त कर लिया जाए एवं 2012 तक शत-प्रतिशत स्वच्छता आच्छांदन की स्थिति प्राप्त कर ली जाए ।

इस कार्य के निष्पादन के लिए जो भी धनराशि की जरूरत होगी वह भारत सरकार उपलब्ध करायेगी । हमने ग्रामीण स्वच्छता के बजट प्रावधानों को जो वर्ष 2002-03 में मात्र 165

करोड़ रुपये था ,इस वित्त वर्ष में बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये किया है एवं अगले वर्ष 800 करोड़ रुपये किया जा रहा है । यदि आवश्यकता पड़ी तो और भी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी । यह इस बात का द्योतक है कि भारत सरकार इस मुद्दे को कितनी अहमियत देती है । हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें एवं पंचायतें यदि मिलकर इस कार्य को करें तो शीघ्र ही सफलता मिलेगी ।

एक स्वच्छ एवं निर्मल भारत का निर्माण तभी संभव है जब सभी वर्गों की भागीदारी हो । ऐसे विशाल अभियान की सफलता जन भागीदारी से ही हो सकती है । जन भागीदारी को बढ़ाने में हमारी पंचायती राज संस्थाओं एवं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का अहम स्थान है एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' की घोषणा 2 अक्तूबर 2003 को की गई थी । स्वच्छता एवं स्थनीय निकायों की स्वायत्ता दोनों ही गांधी जी को काफी प्रिय थे इसलिए उनके जन्म दिवस पर उनकी प्रेरणा से इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी ।

अनेक दौरों के मूल्यांकन के बाद विगत वर्ष 40 पंचायती राज संस्थाओं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था जो इस वर्ष बढ़कर 770 हो गयी है जिनके प्रतिनिधि आज महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करेंगे । यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे हम प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च महीने में प्रदान करने की कोशिश करेंगे । यदि आवश्यकता पड़ी तो हम राज्य स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करेंगे ।

विगत वर्ष यह पुरस्कार सिर्फ 6 राज्यों की पंचायतों ने पाया था । मुझे खुशी है कि इस वर्ष 14 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु,त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल की पंचायतें इस वर्ष पुरस्कार पा रही हैं । मगर हमें पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक देश के प्रत्येक राज्य की पंचायतें अच्छा कार्य करेंगी एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करेंगी ।

विगत जनवरी मास में राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जहां हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे । उस सम्मेलन में राज्यों के मंत्रियों ने कुछ विशेष प्रस्ताव स्वच्छता कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु रखे थे उनमें से कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले संबंधी समिति की मंजूरी प्राप्त हो गयी है । अब इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान राशि 500/- से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी जाएगी । इसके अलावा प्रत्येक जिले को एक रिवोल्विंग फण्ड दिया जाएगा जो राशि स्व सहायता समूहों एवं दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के बिना किसी ब्याज के ऋण देने आएगी। विद्यालय एवं आंगनवाड़ी शौचालय निर्माण को गतिशीलता देने के लिए सामुदायिक अंशदान के प्रावधान को हटा दिया गया है ।

मुझे विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देशन में हम सब सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे ।

अंत में मैं यहां उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अच्छे कार्य करने पर बधाई देता हूं एवं महामहिम राष्ट्रपति जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि यहां उपस्थित होकर उन्होंने न सिर्फ इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है बल्कि असंख्या ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को अनुप्राणित किया है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे ।

धन्यवाद

जयहिन्द